भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3927
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

अंग्रेजी माध्यम के सरकारी प्राथमिक विद्यालय

3927. **श्री बाबू सिंह कुशवाहा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खोले गए अंग्रेजी माध्यम के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है;
(ख) इन विद्यालयों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा भवन, पुस्तकें, स्मार्ट कक्षाएं जैसी अवसंरचना शामिल है के लिए कितनी कुल धनराशि आवंटित और उपयोग की गई;
(ग) इन विद्यालयों में भर्ती किए गए शिक्षकों की संख्या कितनी है और क्या उन्हें कोई प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा कितने जिलों में उक्त प्रक्रिया पूरी हो चुकी है; और
(घ) क्या सरकार ने इन विद्यालयों के शैक्षिक परिणामों, छात्रों के नामांकन में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नए स्कूल खोलने/मौजूदा स्कूलों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण सहित स्कूलों में बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं की आवश्यकता का आंकलन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपनी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष किया जाता हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य के सभी 75 जिलों में कुल 87,777 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में से 12,279 को अंग्रेजी माध्यम के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्कूल शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं - समग्र शिक्षा और पीएम-श्री योजना (पीएम-श्री) का क्रियान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा स्कूल अवसंरचना को मज़बूत करने हेतु

बुनियादी ढाँचे, जैसे स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, नए/मौजूदा स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, चारदीवारी, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय कक्ष, रैंप, बड़ी मरम्मत, फ़र्नीचर की आपूर्ति और आईसीटी एवं डिजिटल उपाय आदि के सृजन और संवर्द्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के माध्यम से, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें आदि शामिल हैं।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) तैयार करते हैं और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। इस पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा योजना के योजना/कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों और अनुमोदित उपायों के लिए राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार विचार किया जाता है और उसका मूल्यांकन/अनुमोदन किया जाता है।

शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शिक्षकों को मौजूदा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से अंग्रेजी माध्यम के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्थानांतरित किया गया और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के 10622 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल) द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के अंतर्गत परख (समग्र विकास हेतु ज्ञान का निष्पादन मूल्यांकन, समीक्षा एवं विश्लेषण) सर्वेक्षण की स्थापना की गई है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य कक्षा 3, 6 और 9 में प्रत्येक शैक्षिक चरण, अर्थात् बुनियादी, प्रारंभिक और माध्यमिक के अंत में छात्रों की बुनियादी साक्षरता, आधारभूत संख्याज्ञान, भाषा और गणित में अधिगम क्षमता का मूल्यांकन करना है।

सर्वेक्षण प्रति तीन वर्ष में आयोजित किया जाता है, और बीच-बीच में वार्षिक राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। नवीनतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, 4 दिसंबर, 2024 को उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए आयोजित किया गया। परिणाम बुनियादी कौशल में उल्लेखनीय सुधार दर्शाते हैं और प्रदर्शित करते हैं कि कक्षा 3 में, ग्रामीण स्कूलों ने शहरी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन किया है और सरकारी स्कूलों ने गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट https://parakh.ncert.gov.in/prs पर देखी जा सकती है।

*****